मांग संख्या 29

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए सहायक ग्रेड-1 के 56 एवं सहायक ग्रेड-2 के 25 पदों के सृजन हेतु ₹ 170.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,70,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

माननीय उच्च न्यायालय के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 100.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 564.58 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 6,64,58,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 3

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 7.20 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 7,20,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 4

छ.ग. राज्य न्यायिक अकादमी के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 25.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 35,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 5

माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना हेतु न्यायाधीशों के कुल 43 पदों के सृजन हेतु ₹ 800.00 लाख का व्यय संभावित है ।

जिला न्यायालयों में टेक्निकल मैनपॉवर हेतु मासिक संविदा वेतन पर स्वीकृत सिस्टम ऑफिसर के 21 पद एवं सिस्टम असिस्टेंट के 41 पद, कुल 62 पदों को सम्मर्पित करते हुए डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के 54 पदों के सृजन हेतु ₹ 85.00 लाख का व्यय संभावित है ।

राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत 18 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा 32 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालयों के लिए सपोर्टिंग स्टॉफ के पदों के सृजन हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

18 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेतु

क्र.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
1.	रीडर ग्रेड-1	लेवल-9	18
2.	स्टेनोग्राफर	लेवल-7	18
3.	एक्जीक्यूशन क्लर्क	लेवल-6	18

4.	**डिपोजिशन राइटर**	**लेवल–4**	18
5.	**प्रोसेस राइटर**	**लेवल–4**	18
6.	**जमादार**	**लेवल–2**	18
7.	**भृत्य**	**लेवल–1**	18
कुल पद			**126**

<u>32 व्यवहार न्यायाधीश हेतु अमला</u>

क्र.	**पदनाम**	**वेतन मैट्रिक्स**	**पद संख्या**
1.	स्टेनोग्राफर	लेवल–7	32
2.	रीडर ग्रेड–3	लेवल–6	32
3.	एक्जीक्यूशन क्लर्क	लेवल–4	32
4.	डिपोजिशन राईटर	लेवल–4	32
5.	प्रोसेस राईटर	लेवल–4	32
6.	भृत्य	लेवल–1	32
कुल योग			**192**

जिला–महासमुंद, तहसील–बागबाहरा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के न्यायालय की स्थापना के लिए 07 पदों के सृजन हेतु ₹ 26.10 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	**पदनाम**	**वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स**	**पद संख्या**
1.	सिविल न्यायाधीश वर्ग–2	56100–177500	01
2.	स्टेनोग्राफर–3	लेवल–7	01
3.	प्रस्तुतकार	लेवल–6	01
4.	निष्पादन लिपिक	लेवल–4	01
5.	साक्ष्य लेखक	लेवल–4	01
6.	आदेशिका लेखक	लेवल–4	01
7.	भृत्य	लेवल–1	01
कुल योग			**07**

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,11,10,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 6

अधीनस्थ न्यायालयों के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 7

अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 8

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 10.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 20,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 9

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 5,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 10

लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यालयों के लिए पुस्तकों के क्रय हेतु ₹ 11.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 11,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 11

परिवार न्यायालयों के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 10.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 20,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 12

परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 13

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय तथा WAN Connection के देयकों के भुगतान हेतु ₹ 619.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 6,19,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 14

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिए लैपटॉप तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 20,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 15

माननीय उच्च न्यायालय में 01 ए.डी.आर. सेंटर एवं 8 जिला न्यायालय में 08 ए.डी. आर. सेंटर के भवन निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

जिला एवं अधिनस्थ न्यायालयों हेतु न्यायिक भवन के निर्माण हेतु ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 11,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 16

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर के भवन निर्माण एवं अन्य रख रखाव के विभिन्न कार्यो हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक 17

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं रजिस्ट्री के अधिकारियों हेतु 04 नग नवीन वाहन के क्रय हेतु ₹ 53.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 53,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 18

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के एडीशनल डायरेक्टर के उपयोग हेतु 01 नग वाहन के क्रय हेतु ₹ 7.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 7,50,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत विशेष न्यायालयों के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 5.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत विशेष न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 9.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 9,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर में 7 नग कोर्ट रूम निर्माण कार्य के अंतर्गत आंतरिक साज सज्जा हेतु ₹ 625.63 लाख का व्यय संभावित है ।

महाधिवक्ता कार्यालय भवन बोदरी, बिलासपुर में तृतीय तल भवन निर्माण हेतु ₹ 117.25 लाख का व्यय संभावित है ।

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों हेतु न्यायिक भवनों के निर्माण के लिए ₹ 4500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 52,42,88,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4216

मद क्रमांक 2

उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 1500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 15,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 3

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बी टाईप-05, सी टाईप-08, डी टाईप-45, ई टाईप-40, एफ टाईप-50, जी टाईप-255, एच टाईप-400 एवं आई टाईप-420, कुल 1223 आवासीय भवन निर्माण की कुल लागत ₹ 22933.36 लाख अनुमानित है। इस वर्ष ₹ 7000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 70,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।